

देवकी नंदन

बनाम

मुरलीधर

[जगन्नाथ, वैकटरामा अय्यर, बी. पी. सिन्हा और एस. के. दास जेजे]

हिंदू कानून-धार्मिक दान-मंदिर सामाजिक और निजी, तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न मूर्ति को उपहार-क्या पुजारी लाभार्थी हैं-जनता को भेंट वसीयत का निर्माण-मूर्ति की स्थापना से संबंधित समारोह-मंदिर का उपयोगकर्ता।

यह मुद्दा कि क्या एक धार्मिक दान एक सार्वजनिक या एक निजी दान है, कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्णय पाए गए तथ्यों के लिए एक सार्वजनिक और एक निजी दान की कानूनी अवधारणाओं के अनुप्रयोग पर निर्भर होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए खुला है।

लक्ष्मीधर मिश्रा बनाम। रंगलाल ([1949] एल. आर. 76 आई. ए. 271) को वापस ले जाया गया। निजी और सार्वजनिक धर्मदाय के बीच अंतर यह है कि जहां पहले में लाभार्थी विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, वहीं बाद में वे आम जनता या उसका एक वर्ग होते हैं।

हालांकि हिंदू कानून के तहत एक मूर्ति एक न्यायिक व्यक्ति है जो संपत्ति रखने में सक्षम है और उसमें मंदिर के लिए दान की गई संपत्तियों

का दान में कोई लाभकारी हित नहीं हो सकता है, और सच्चे लाभार्थी उपासक हैं, क्योंकि किसी मूर्ति को संपत्ति के उपहार का वास्तविक उद्देश्य भगवान को कोई लाभ प्रदान करना नहीं है, बल्कि पूजा करने की इच्छा रखने वालों के लिए सुविधाएँ एवं अवसर प्रदान करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है।

प्रोसुन्नो कुमारी देब्या बनाम गुलाब चंद बाबू ([1875] एल. आर. 2 आई. ए. 145), महाराजा जगदीन्द्र नाथ राय बहादुर बनाम। रानी हेमंत कुमारी देवी ([1904] एल. आर. 31 आई. ए. 203), प्रमथ नाथ मुल्लिक बनाम। प्रद्युम्न कुमार मुल्लिक ([1924] एल. आर. 52 आई. ए. 245) और भूपति नाथ स्मृतितीर्थ बनाम राम लाल मैत्र ([1910] आई. एल. आर. 37 कैल. 128), संदर्भित किया गया।

एक पवित्र हिंदू, जो निःसंतान था, ने एक मंदिर का निर्माण किया और अपनी मृत्यु तक इसके प्रबंधन में। उन्होंने एक वसीयत का निष्पादन किया जिसके तहत उन्होंने अपनी सम्पूर्ण भूमि मंदिर को विरासत में दी और उसके उचित प्रबंधन के लिए प्रावधान किया। सवाल यह था कि क्या इसके प्रावधान वसीयतकर्ता की ओर से समर्पण करने के प्रयोजन का खुलासा जनता के लिए या केवल परिवार के सदस्यों के लिए मंदिर करेगा।

निर्धारित, कि वसीयत में पाठ कि वसीयतकर्ता के कोई संतानें नहीं थी, अपरिचितों द्वारा न्यास के प्रबंधन के प्रावधानों के साथ मिलकर यह एक संकेत था कि समर्पण जनता के लिए था।

नबी शिराजी बनाम बंगाल प्रांत (आई. एल. आर. [1942] 1 कैल. 211) , संदर्भित किया गया।

आगे आयोजित किया गया कि कॉन में समारोहों का प्रदर्शन मंदिर का संरक्षण (प्रथिस्ता), मंदिर का उपयोग करने वाला और अन्य मामले में साक्ष्य से पता चला कि समर्पण आम जनता की पूजा के लिए था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 250 1953 में।

ऑंध के मुख्य न्यायालय, लखनऊ के फैसले और डिक्री से अपील जुलाई 14, 1948 में नियमित दीवानी मुकदमा संख्या 14 में सिविल न्यायाधीश, सीतापुर।

ए. डी. माथुर, अपीलार्थी के लिए।

जगदीश चंद्र, प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए।

1956. 4 अक्टूबर। न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था।

वेंकटरामा अय्यर जे.-निर्णय का मुद्दा इस अपील में यह है कि क्या श्री का ठाकुरद्वारा है।

सीतापुर जिले के भदेसिया गाँव में राधाकृष्णजी एक निजी मंदिर या सार्वजनिक मंदिर है जिसमें सभी हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है।

एक शीओ गुलाम, एक पवित्र हिंदू और निवासी

उक्त गाँव ने वर्षों 1914-1916 के दौरान ठाकुरद्वारा का निर्माण किया था, और उसमें श्री राधाकृष्णजी की मूर्ति को औपचारिक रूप से स्थापित

किया गया था। 1928 में बिना किसी समस्या के उनकी मृत्यु होने तक वे स्वयं मंदिर और उसके मामलों के प्रबंधन में थे। 6 मार्च, 1919 को उन्होंने एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसके तहत उन्होंने अपनी सारी जमीन ठाकुर को विरासत में दी थी।

वसीयतनामा के संकेत, जहाँ तक वे भौतिक हैं, वर्तमान में संदर्भित किए जाएंगे। वसीयतकर्ता की दो पत्नियाँ थीं, जिनमें से एक राम कुर उनकी मृत्यु से पहले हो चुकी थी और जीवित विधवा, राज कुर, वसीयत के मामले में मुतवल्ली के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने और 1933 में अपनी मृत्यु तक प्रबंधन में रहीं। फिर पहला प्रतिवादी, जो शीओ गुलाम का भतीजा है, वसीयत के प्रावधानों के अनुसार धर्मदाय के प्रबंधक के रूप में संपत्तियों का अधिग्रहण कर लेता है। अपीलार्थी शीओ गुलाम का एक दूर का प्रतिनिधि है, और इस आरोप पर कि पहला प्रतिवादी मंदिर का गलत प्रबंधन कर रहा था और उसमें जनता के अधिकारों से इनकार कर रहा था, उसने 1920 के धार्मिक और हिन्दू धर्मदाय अधिनियम XIV के तहत राहत के लिए सीतापुर के जिला न्यायालय का रुख किया, लेकिन अदालत ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि धर्मदाय निजी थी। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमा दायर करने की मंजूरी के लिए महाधिवक्ता को आवेदन को भी इसी कारण से अस्वीकार कर दिया गया था। अपीलार्थी ने तब मुकदमा दायर किया, जिसमें से वर्तमान अपील यह घोषणा करने के लिए प्रस्तुत की है कि ठाकुरद्वारा एक

सार्वजनिक मंदिर है जिसमें सभी हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है। पहले प्रतिवादी ने मुकदमे का विरोध किया, और दावा किया कि "ठाकुर द्वार और मूर्तियाँ निजी थीं", और "आम जनता को कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था"।

एस सी आर।

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, सीतापुर, जहां विचारण हुआ, जिन्होंने मुकदमा चलाया जिनकी राय थी कि ठाकुरद्वारा का निर्माण शीओ गुलाम ने "अपने परिवार द्वारा पूजा के लिए" किया था और कि यह एक निजी मंदिर था।

इस फैसले की पुष्टि की गई थी और मुकदमा खारिज कर दिया। जिला न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा अपील, जिनके फैसले की द्वितीय अपील में अवध के मुख्य न्यायालय द्वारा फिर से पुष्टि की गई थी। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीशों ने एस के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया। 109 (ग) सिविल प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि इसमें हस्तगत प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और इस तरह से अपील की जाती है।

इस अपील में निर्णय के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है कि भदेसिया में श्री राधाकृष्ण जी का ठाकुरद्वारा सार्वजनिक दान है या निजी, यह मिश्रित कानून और तथ्यों में से एक है। लक्ष्मीधर मिश्रा बनाम। रंगलाल (1), जिसमें सवाल यह था कि क्या कुछ भूमि को श्मशान के रूप में

समर्पित किया गया था, प्रिवी काउंसिल द्वारा यह देखा गया था कि यह "सार" था।

कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न ", और यह कि जबकि निचली अपीलीय अदालत के तथ्य के निष्कर्षों को बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, इसका" वास्तविक निष्कर्ष कि कोई भेंट या खोया हुआ अनुदान है, अधिक उचित रूप से प्राप्त कानून के प्रस्ताव के रूप में माना जाता है।

उन तथ्यों से बल्कि तथ्य की खोज के रूप में "वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया गया था कि एक औपचारिक समर्पण था; और विवाद केवल समर्पण के दायरे के बारे में है, और यह कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न भी है, जिसका निर्णय पाए गए तथ्यों के लिए सार्वजनिक और निजी दान की कानूनी अवधारणाओं के अनुप्रयोग पर निर्भर होना चाहिए, और यह इस अपील में विचार के लिए खुला है।

पहले सिद्धांतों पर विचार करना सुविधाजनक होगा।

इस प्रश्न के निर्धारण के लिए लागू विधि की कि क्या कोई धर्मदाय सार्वजनिक है या निजी, और फिर उन सिद्धांतों के आलोक में, पाए गए या स्थापित तथ्यों की जांच करना निजी और सार्वजनिक न्यास के बीच का अंतर यह है कि जहां पहले वाले में लाभार्थी विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, वहीं

बाद वाले में वे आम जनता या उसका एक वर्ग होते हैं। जबकि पूर्व में लाभार्थी वे व्यक्ति हैं जो हैं।

(1) [1949] एल. आर. 76 आई. ए. 271।

अभिनिर्धारित या अभिनिर्धारित किए जाने में सक्षम, बाद में वे एक निकाय का गठन करते हैं जो अभिनिर्धारित करने में असमर्थ है। इस प्रकार स्थिति ट्रस्ट पर लेविन, पंद्रहवें संस्करण, पीपी में बताई गई है। 15-16 :

" जनता से यह समझना चाहिए कि वे किसी विशेष विवरण का उत्तर देते हुए या तो बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए या इसके कुछ बड़े हिस्से के लिए निर्धारित किया गया है। इस वर्ग के सभी न्यास धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए हैं, और वास्तव में सार्वजनिक न्यासों और धर्मार्थ न्यासों को सामान्य रूप से पर्यायवाची अभिव्यक्तियों के रूप में माना जा सकता है। निजी न्यासों में लाभकारी हित पूरी तरह से एक या अधिक लाभांशधारियों में निहित होता है, जो निश्चित रूप से निश्चित हैं या एक निश्चित समय के भीतर निश्चित किए जा सकते हैं। नबी शिराजी बनाम में जे. मित्तर की टिप्पणियों को भी देखें। बंगाल प्रांत (1)। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, एक धार्मिक दान को निजी या सार्वजनिक माना जाना चाहिए, क्योंकि इसके तहत लाभार्थी विशिष्ट व्यक्ति या आम जनता या उसके अनुभाग हैं।

फिर सवाल यह है कि लाभार्थी कौन हैं?

जब कोई मंदिर बनाया जाता है, तो उसमें मूर्ति स्थापित की जाती है और उसके लिए उपहार दिए जाते हैं? हिंदू कानून के तहत, एक मूर्ति एक न्यायिक व्यक्ति है जो संपत्ति रखने में सक्षम है और संस्था के लिए दान की गई संपत्तियां उसमें निहित हैं। लेकिन क्या इससे यह पता चलता है कि इसे दान का लाभकारी स्वामी माना जाना चाहिए? यद्यपि एक समय में इस तरह की धारणा का प्रचलन था, और इन कार्यवाहियों में इसकी प्रतिध्वनि है (वाद के पैरा 15 के अनुसार), अब यह सभी विवादों से परे स्थापित हो गया है कि यह सही स्थिति नहीं है। यह समय-समय पर माना गया है कि यह केवल एक आदर्श अर्थ में है कि मूर्ति संपन्न संपत्तियों की मालिक है। प्रोसुनो कुमारी देब्या बनाम। गुलाब चंद बाबू (3); महाराजा जगदीन्द्र नाथ राय बहादुर बनाम। रानी हेमंत कुमारी देवी और प्रमथ नाथ मुल्लिक बनाम। प्रद्युम्न कुमार मलिक (1)। यह स्वयं उनका उपयोग नहीं कर सकता है; यह उनका आनंद नहीं ले सकता है या उनका निस्तारण नहीं कर सकता है, या उनकी रक्षा भी नहीं कर सकता है। संक्षेप में, मूर्ति का दान में कोई लाभकारी हित नहीं हो सकता है। यह संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित स्पष्ट था। इस प्रकार, पूर्व मीमांसा पर अपने भाष्य, अध्याय 9, पद 1 में, सबरा स्वामी के निम्नलिखित शब्द हैं:

देवग्रामो, दे वक्षेत्रामती, उपचर्मात्रम। यो यध्वी प्रे रे तीवती योक्।

मृत्यु से धन्यवाद.....।

वह जीवन में सबसे पहले हो सकता है।

" देवताओं की संपत्ति, देवस्वम, का अर्थ है जो कुछ भी देवताओं के लिए त्याग दिया जाता है, बलिदान और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए, क्योंकि प्राथमिक अर्थों में स्वामित्व, जैसे -

स्वामी और स्वामित्व वाली संपत्ति के बीच संबंध दिखाना, देवताओं के लिए लागू करना असंभव है। क्योंकि देवता अपनी इच्छा के अनुसार संपत्ति का उपयोग नहीं करते हैं और न ही उन्हें उसी के लिए काम करते हुए देखा जाता है।

इस प्रकार, ग्रंथों के अनुसार, देवताओं को संपत्तियों का कोई लाभ नहीं है, और उन्हें केवल एक आलंकारिक अर्थ में उनके मालिकों के रूप में माना जा सकता है। (गौनरथ), और मूर्ति को उपहार के उपहार का वास्तविक उद्देश्य भगवान को कोई लाभ प्रदान करना नहीं है, बल्कि अवसर प्रदान करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना है।

पूजा करने की इच्छा रखने वालों के लिए उपहार और सुविधाएं।

भूपति नाथ स्मृतितीर्थ बनाम। राम लाल मैत्र (1), इन और अन्य ग्रंथों पर विचार करते हुए यह माना गया था कि एक मूर्ति को उपहार एक 'संवेदनशील व्यक्ति' को हस्तांतरण के लिए लागू नियमों द्वारा नहीं आंका जाना था, और एक मूर्ति को संपत्तियों का समर्पण में शामिल था

उन पर अपने प्रभुत्व के मालिक द्वारा उनका त्याग इस उद्देश्य से किया जाता है कि उन्हें उस उद्देश्य के लिए विनियोजित किया जाए जो वह चाहता है। इस प्रकार, यह सर लॉरेंस जेनकिंस सी. जे. द्वारा पी. 138 कि "पवित्र उद्देश्य अभी भी उत्तराधिकारी है, की छवि केवल वह तरीका है जिसमें पवित्र उद्देश्य प्रभावित होता है। "और यह कि" किसी देवता को समर्पण "" पवित्र पुर मुद्राओं की एक सारगर्भित अभिव्यक्ति हो सकती है जिसके लिए समर्पण तैयार किया गया है "। पी में सर आशुतोष मुखर्जी की टिप्पणियों को भी देखें। 155 . हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड v. वीरराघव चरियार (3), वरदाचारियार जे. ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए, भूपति नाथ स्मृति तीर्थ बनाम में निर्णय का उल्लेख किया। राम लाल मैत्र (ऊपर) ने कहा:

" जैसा कि उस मामले में समझाया गया है,

किसी मंदिर को उपहार देने का अर्थ भगवान को लाभ प्रदान करना नहीं है, बल्कि उस मंदिर में पूजा करने वालों को लाभ प्रदान करना है, ताकि उनके लिए उचित और प्रभावशाली तरीके से पूजा करना संभव हो सके। यही वह अर्थ है जिसमें एक मंदिर और उसके दान को एक सार्वजनिक न्यास माना जाता है।

जब एक बार यह समझाया गया है कि सच्चा लाभ धार्मिक दान के संरक्षक मूर्तियाँ नहीं बल्कि उपासक होते हैं, और यह कि दान का उद्देश्य उपासकों के लाभ के लिए उस पूजा का रखरखाव है, यह प्रश्न कि क्या दान

निजी है या सार्वजनिक, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यह तय करने का मुख्य बिंदु यह है कि क्या यह संस्थापक का प्रयोजन था कि निर्दिष्ट व्यक्तियों को मंदिर, या आम जनता या उसके किसी निर्दिष्ट हिस्से में पूजा का अधिकार होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार, यह माना गया है कि जब संपत्ति को पारिवारिक मूर्ति की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है, तो यह एक निजी और सार्वजनिक दान नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति देवता के मंदिर में पूजा करने के हकदार हैं, वे केवल परिवार के सदस्य हो सकते हैं और यह व्यक्तियों का एक निश्चित समूह है। लेकिन जहां लाभार्थी किसी परिवार के सदस्य या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं हैं, तो दान को केवल सार्वजनिक माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य उपासकों का सामान्य निकाय परिवार को लाभ पहुंचाना है।

इन सिद्धांतों के आलोक में, हमें जांच करनी चाहिए।

इस मामले के तथ्य। इस सवाल पर आधारित सामग्री कि ठाकुरद्वारा एक सार्वजनिक मंदिर है या एक निजी मंदिर, चार शीर्षों के तहत विचार किया जा सकता है: (1) शीओ गुलाम की वसीयत प्रदर्श ए-1, (2) जनता द्वारा मंदिर का उपयोगकर्ता, (3) संबंधित समारोह ठाकुरद्वारा का समर्पण और संकल्प और उथसरग के विशेष संदर्भ में मूर्ति की स्थापना, और (4) मंदिर के चरित्र से संबंधित अन्य तथ्य।

(1) वसीयत, प्रदर्श ए-1, सबसे महत्वपूर्ण है।

वसीयतकर्ता के प्रयोजन और समर्पण के दायरे के रूप में अभिलेख पर साक्ष्य। इसके प्रावधान, जहाँ तक वे सामग्री हैं, अब ध्यान दिए जा सकते हैं। वसीयत की शुरुआत इस तथ्य से होती है कि वसीयतकर्ता की दो पत्नियाँ हैं और कोई पुरुष संतान नहीं है, कि उसने एक ठाकुर द्वारा का निर्माण किया है और उसमें श्री राधाकृष्णजी की मूर्ति स्थापित की है, और वह विवादों से बचने के लिए संपत्तियों का निपटान कर रहा है। प्रदर्श ए-1 के खंड 1 में प्रावधान है कि पुरुष निर्गम के अभाव में वृषण की मृत्यु के बाद, नीचे दी गई पूरी अचल संपत्ति जो वर्तमान में अस्तित्व में है या जो इसके बाद अस्तित्व में आ सकती है, श्री राधाकृष्णजी के नाम पर संपन्न होगी और नामों का परिवर्तन श्री राधा के पक्ष में किया जाएगा।

सरकारी दस्तावेजों में कृष्णाजी और मेरी पत्नियाँ श्रीमती। राज कुएर और एमएसटी। राम कुर वक्फ के मुतावाली होंगे। संपत्तियाँ से होने वाली आय का आधा हिस्सा दोनों पत्नियों को अपने जीवनकाल के दौरान अपने भरण-पोषण के लिए लेना था, और शेष आधा "ठाकुरद्वारे के खर्चों के लिए खर्च किया जाना था"। इस प्रावधान में यह निहित है कि पत्नियों के जीवनकाल के बाद, पूरी आय का उपयोग ठाकुर द्वार के उद्देश्य के लिए किया जाना है। खंड 4 में प्रावधान है कि यदि एक पुत्र का जन्म होता है वसीयतकर्ता, फिर संपत्तियों को बेटे और ठाकुरद्वारे के बीच एक निर्दिष्ट शर्त में विभाजित किया जाना है

अनुपात; लेकिन चूंकि कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था, इसलिए यह खंड कभी लागू नहीं हुआ। खंड 5 में प्रावधान है कि -

मुतावल्लियों के पास संपत्ति को बेचने या गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कि वे खातों का रखरखाव करें, कि खर्चों को पूरा करने के बाद अधिशेष धन को एक सुरक्षित बैंक में जमा किया जाना चाहिए और जब धन अनुमति देता है, तो संपत्ति श्री राधाकृष्णजी के नाम पर खरीदी जानी चाहिए। खंड 2 मंदिर और उसकी संपत्तियों के प्रबंधन की देखरेख के लिए चार व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करता है, और इनमें से दो वसीयतकर्ता के संबंध नहीं हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। जाति। उस खंड में आगे यह प्रावधान किया गया है कि दोनों पत्नियों की मृत्यु के बाद समिति "अपने सर्वसम्मत विचार से मेरे भतीजे मुरलीधर को मुतावल्ली के रूप में इंगित कर सकती है"। यह मुरलीधर एक विभाजित है वसीयतकर्ता का भतीजा और वह इस कार्रवाई में पहला प्रतिवादी है। खंड 3 समिति में रिक्तियों को भरने का प्रावधान करता है। फिर अंत में सी. एल. है। 6 , जो इस प्रकार से है कि

" यदि कोई व्यक्ति खुद को मेरा निकट या दूरस्थ उत्तराधिकारी होने का आरोप लगाते हुए वक्फ संपत्ति के पूरे या कुछ हिस्से के संबंध में दावा प्रस्तुत करता है तो उसका मुकदमा इस विलेख के बावजूद अनुचित होगा। सवाल यह है कि क्या वसीयत के प्रावधान वसीयतकर्ता की ओर से एक प्रयोजन का खुलासा करते हैं कि ठाकुरद्वारा एक निजी दान होना चाहिए,

या यह सार्वजनिक होना चाहिए। न्यायालयों के निर्णयों की पुष्टि करने में मुख्य न्यायालय के निचले विद्वान न्यायाधीश कि मंदिर परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए बनाया गया था, यह देखा गया कि वसीयत में "इस निष्कर्ष की ओर इंगित नहीं किया गया था कि न्यास एक सार्वजनिक था", और यह कि इसके प्रावधान "संपत्ति के निजी दान होने के साथ असंगत नहीं थे"। हम इस राय का समर्थन करने में असमर्थ हैं। हम सोचते हैं कि समग्र रूप से पढ़ी जाने वाली वसीयत निर्विवाद रूप से वसीयतकर्ता की ओर से ठाकुरद्वारा को जनता को समर्पित करने के इरादे को प्रकट करती है, न कि केवल अपने परिवार के सदस्यों को।

वसीयतकर्ता यह कहते हुए शुरू करता है कि उसके पास नहीं था

पुरुष मुद्दा। नबी शिराजी बनाम। बंगाल प्रांत (ऊपर), सवाल यह था कि क्या वर्ष 1806 के एक विलेख द्वारा बनाया गया वक्फ सार्वजनिक था या निजी दान था।

दान विलेख में एक पाठ का उल्लेख करते हुए कि जे. खुंडकर ने कहा कि बसने वाले की कोई संतान नहीं थी।

पी। 217 :

" विलेख में कहा गया है कि संस्थापक के पास न तो बच्चे और न ही पोते-पोतियां, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें स्वयं यह सुझाव देते हैं कि इमामबाड़ा को एक निजी या पारिवारिक संस्थान नहीं रहना था।

पी. पर जे. मित्तर की टिप्पणियों को भी देखें। 228. उपरोक्त दृष्टिकोण जिस तर्क पर आधारित है, ओ. बी.

उत्साहपूर्वक, कि 'परिवार' शब्द अपने लोकप्रिय अर्थ में मतलब बच्चे, और जब बसने वाला पाठ करता है कि वह कोई संतान नहीं है, यह एक संकेत है कि यह परिवार के लाभ के लिए नहीं बल्कि परिवार के हित के लिए है। फिर हमारे पास खंड 2 है, जिसके तहत वसीयतकर्ता प्रबंधन की एक समिति का गठन किया जाता है जिसमें चार व्यक्ति होते हैं, जिनमें से दो पूरी तरह से उनसे असंबंधित थे। खंड 3 समिति को रिक्तियों को भरने की शक्ति प्रदान करता है; लेकिन इसमें उन व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्हें उस खंड के तहत नियुक्त किया जा सकता है, और संभवतः, सभी चार सदस्य भी परिवार के लिए अजनबी हो सकते हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है कि अगर शीओ गुलाम का इरादा अधिकार को प्रतिबंधित करना था मंदिर में अपने रिश्तेदारों को जहाज, उसने उसका प्रबंधन अपरिचितों से युक्त एक निकाय को सौंपा होगा। अंत में, खंड 6 है, जो दर्शाता है कि शीओ गुलाम और उसके रिश्तेदारों के बीच संबंध विशेष रूप से सौहार्दपूर्ण नहीं थे, और यह उल्लेखनीय है कि खंड 2 के तहत, यहां तक कि पहले प्रतिवादी की नियुक्ति को भी समिति के विकल्प पर छोड़ दिया जाता है।

यह अकल्पनीय है कि अपने संबंधों के लिए इतने कम आग्रह के साथ, शीओ गुलाम ने उनके लाभ के लिए एक मंदिर प्रदान किया होगा। और यदि वह उन्हें धर्मदाय के तहत लाभार्थी नहीं बनाना चाहता था, तो

परिवार के कौन सदस्य हैं जो उसकी दो पत्नियों के जीवनकाल के बाद इसके तहत लाभ ले सकते हैं? अगर हमें यह मानना है कि दान परिवार के सदस्यों के पक्ष में था, तो परिणाम यह होगा कि दोनों पत्नियों की मृत्यु पर, यह वस्तुओं के अभाव में विफल होना चाहिए। लेकिन वसीयत के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता ने उसकी पत्नियों के जीवनकाल से परे दान का को जारी रखने पर विचार किया।

उन्होंने निर्देश दिया कि संपत्तियों को देवता के नाम पर दिया जाना चाहिए और भविष्य में देवता के नाम पर जमीनें खरीदी जानी चाहिए। वह अपनी पत्नियों के जीवनकाल के बाद न्यास के प्रबंधन का भी प्रावधान करता है। और इसे लागू करने के लिए, यह मानना आवश्यक है कि ठाकुरद्वारा जनता के सदस्यों द्वारा पूजा के लिए समर्पित किया गया था, न कि केवल उनके परिवार के लिए। यह निर्णय लेने में कि दान एक निजी था, मुख्य न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश इन पहलुओं का विज्ञापन करने में विफल रहे, और हम उनके निर्णय को सही के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

2. ठाकुरद्वाराक प्रतिष्ठापनक विलेख करवाने के अभाव में, वादी जनता द्वारा मंदिर के उपयोगकर्ता समर्पणक वास्तविक दायरा स्थापित करबाक प्रयास किया। उसकी ओर से खनन करने वाले गवाहों ने गवाही दी कि ग्रामीण स्वतंत्र रूप से और बिना किसी हस्तक्षेप के मंदिर में पूजा कर रहे थे, और वास्तव में, यह भी कहा गया था कि ठाकुरद्वारा का निर्माण शिव

गुलाम ने ग्रामीणों के कहने पर किया था, क्योंकि गाँव में कोई मंदिर नहीं था। विचारण न्यायाधीश ने इस साक्ष्य को विश्वास के अभाव के रूप में खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने माना कि पी. डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य से लिया जाने वाला उचित निष्कर्ष यह था कि जनता को मंदिर में अधिकार के रूप में नहीं बल्कि अनुग्रह के रूप में प्रवेश दिया गया था। पी. डब्ल्यू. 2 मंदिर में पुजारी था, और उसने अपदस्थ कर दिया कि जब शीओ गुलाम की पत्नी मंदिर के भीतर पूजा कर रही थी, तो उसने उन बाहरी लोगों को अंदर जाने से रोक दिया जिनकी उपस्थिति में वह पर्दा रखती थी। हमारी राय है कि यह तथ्य इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त आधार नहीं देता है कि ग्रामीणों ने अधिकार के रूप में मंदिर में पूजा नहीं की थी। यह कुछ भी असामान्य नहीं है कि प्रसिद्ध सार्वजनिक मंदिरों में भी पूजा कक्ष को जनता से हटा दिया जाता है जब एक उच्च गणमान्य व्यक्ति पूजा के लिए आता है, और जनता को रोकने में पुजारी का कार्य उस सम्मान की अभिव्यक्ति है जो पूरे ग्रामीणों को संस्थापक की पत्नी के लिए था, जो पूजा के लिए आने पर एक क्षमाशील महिला थी, और इसे उनके अधिकारों से इनकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। मुख्य न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने भी एस. सी. आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के निर्णय को आधार लिया। बाबू भगवान दिन बनाम में प्रिवी काउंसिल। गिर हर सरून (1) इस स्थिति के लिए एक प्राधिकरण के रूप में कि "केवल यह तथ्य कि जनता को किसी मंदिर या ठाकुरद्वारे में जाने की अनुमति है, यह आवश्यक रूप से

इंगित नहीं कर सकता है कि न्यास निजी के विपरीत सार्वजनिक है"। उस मामले में, कुछ संपत्तियां एक मूर्ति या मंदिर के पक्ष में नहीं दी गई थीं, बल्कि एक दरियाव गिर के पक्ष में दी गई थीं, जो एक मंदिर का रखरखाव कर रहा था और उसके उत्तराधिकारियों को प्रति पेच्युटी में। जनता का तर्क था कि अनुदान के बाद दरियाव गिर के परिवार को पूजा के उद्देश्य से मंदिर को जनता को समर्पित करने के लिए माना जाना चाहिए, और जनता के सदस्यों को मंदिर में पूजा करने और प्रसाद चढ़ाने की अनुमति इस तरह के समर्पण के प्रमाण में दी गई थी। इस तर्क को खारिज करते हुए, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि चूंकि अनुदान शुरू में एक व्यक्ति को दिया गया था, इसलिए एक याचिका है कि बाद में यह दिया गया था।

परिवार द्वारा आवश्यक जनता को समर्पित

यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, और यह केवल यह दिखाने से नहीं बनाया गया था कि जनता को मंदिर में पूजा करने की अनुमति थी "क्योंकि यह सामान्य रूप से हिंदू भावनाओं या प्रथा के अनुरूप नहीं होगा कि पूजा को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए"। लेकिन, वर्तमान मामले में, दान स्वयं मूर्ति के पक्ष में था, और निर्णय का मुद्दा यह है कि क्या यह एक निजी या सार्वजनिक दान था। और ऐसी परिस्थितियों में, बिना किसी हस्तक्षेप के जनता द्वारा उपयोगकर्ता का प्रमाण इस बात का ठोस सबूत होगा कि समर्पण जनता के पक्ष में था

मुंडांचेरी कोमन बनाम। अच्युतन (3), जिसे बाबू भगवान दिन बनाम गिर हर सरून (1) में संदर्भित और अनुसरण किया गया था, एक संस्था के संबंध में उपयोगकर्ता के बीच अंतर जो शुरू में साबित होता है।

" क्या रखने का कोई पर्याप्त कारण था। निजी होना और जो नहीं है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि ये मंदिर और उनके दान मूल रूप से तरवाड़ के लिए समर्पित थे, और इसी तरह निजी ट्रस्ट भी थे, उनके प्रभुता यह मानने में धीमी रही होगी कि बाद के समय में जनता का प्रवेश होता है। संभवतः परिवर्तित स्थितियों के कारण, न्यासों के निजी चरित्र को प्रभावित करेगा।

3. यह तय किया गया कानून है कि किसी विशेष समारोह के प्रदर्शन के बिना एक मूर्ति या मंदिर के पक्ष में एक धर्मदाय वैध रूप से बनाई जा सकती है, बशर्ते कि बसने वाले ने उस ओर से स्पष्ट और स्पष्ट रूप से अपना प्रयोजन व्यक्त किया हो। जहां यह साबित हो जाता है कि समारोह किए गए थे, वह दान का मूल्यवान प्रमाण होगा, लेकिन इस तरह के प्रमाण का अभाव इसके खिलाफ निर्णायक नहीं होगा। वर्तमान मामले में, यह सामान्य आधार है कि मंदिर का अभिषेक और श्री राधाकृष्णजी की मूर्ति की स्थापना बड़ी गंभीरता के साथ और शास्त्रों के अनुसार की गई थी। पी. डब्ल्यू. 10, जिन्होंने समारोह में आचार्य के रूप में शपथ ली थी, ने अपदस्थ किया है कि यह सात दिनों तक चला और कलश पूजा से शुरू होने वाले और स्थापना या प्रतिष्ठा के साथ समाप्त होने वाले सभी समारोहों

को विधिवत किया गया और श्री राधाकृष्णजी, श्री शिवजी और श्री हनुमानजी की मूर्तियों को प्रथिस्त मयूख में निर्धारित किया गया था। इस साक्ष्य पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रतिवादी समर्पण और समारोह दोनों को स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल इस बात पर विवाद करते हैं कि समर्पण जनता के लिए था। निचली अदालत में, अपीलार्थी ने यह संकेत दिया कि उत्सव समारोह का प्रदर्शन अभिषेक के समय यह दिखाने के लिए निर्णायक था कि समर्पण जनता के लिए था, और जैसा कि पी. डब्ल्यू. 10 ने कहा कि प्रसादोत्सर्ग किया गया था, दान को सार्वजनिक माना जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो एक आधिकारिक निर्णय की मांग करता था, और इस कारण से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 (सी) के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हमने स्वयं इस प्रश्न से संबंधित संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा है, और हमारी राय है कि अपीलार्थी का तर्क एक गलत धारणा पर आगे बढ़ता है। समर्पण समारोहों में संकल्प, उत्सव और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट शामिल हैं।

संकल्प का अर्थ है दृढ़ संकल्प, और वास्तव में यह अपने इरादे के निर्धारक द्वारा एक औपचारिक घोषणा है।

संपत्ति को समर्पित करना। उत्सर्ग संपत्ति में अपने स्वामित्व के संस्थापक द्वारा औपचारिक त्याग है, जिसका परिणाम यह है कि यह उस विश्वास से प्रभावित हो जाता है जिसके लिए वह इसे समर्पित करता है।

आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से,
आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से,
आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से,
आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से,
आपकी वजह से, आपकी वजह से।

यह देखा जाएगा कि यह केवल उत्सव के बिना संकल्प है, और इसमें कोई शब्द नहीं हैं जो दर्शाते हैं कि समर्पण जनता के लिए है। वास्तव में, ग्रंथों के अनुसार, उत्सव केवल धर्मार्थ दान के लिए किया जाना है, जैसे कि तालाबों का निर्माण, उद्यानों का पालन और इसी तरह, न कि धार्मिक नींव के लिए। यह श्री मंडलिक द्वारा व्यवहार मयूख, भाग ॥, परिशिष्ट ॥, पी में मनाया गया है।

"मंदिर का कोई उत्सव नहीं है सिवाय इसके कि पुराने मंदिरों की मरम्मत का मामला "। धर्मशास्त्रों के इतिहास में, खंड ॥, भाग ॥, पी। 893 , श्री केन ने बताया कि मंदिरों के मामले में उपयोग करने के लिए प्रति शब्द प्रथिस्त है न कि उत्सर्ग। इससे पहले, मंदिरों के मामले में उत्सर्ग समारोह के प्रदर्शन के कारण जनता के प्रति समर्पण का अनुमान लगाने का प्रश्न नहीं उठ सकता है। अपीलार्थी अपन एहि तर्कमे सही अछि जे यदि उत्सर्ग कयल जाइत अछि तँ समर्पण जनताक लेल अछि, मुदा हुनक तर्कमे भ्रान्ति उत्सर्गक सङ्ग प्रसादोत्सर्गक तुलना करबामे निहित अछि। लेकिन ग्रंथों से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिष्ठा मंदिरों के समर्पण में

उथर्गा की जगह लेता है, और यह कि श्री राधा कृष्णजी का प्रतिष्ठा था जैसा कि पी. डब्ल्यू. 10 द्वारा कहा गया था, विवाद में नहीं है। हमारी राय में, यह स्थापित करता है कि समर्पण जनता के लिए था।

(4) अब हम स्वीकार किए गए कुछ तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं या साक्ष्य में स्थापित, जो इंगित करता है कि दान जनता के लिए है। सबसे पहले, यह तथ्य है कि मूर्ति आवासीय आवासों के परिसर के भीतर नहीं, बल्कि एक खाली स्थान पर उसी उद्देश्य के लिए बनाई गई एक अलग इमारत में स्थापित की गई थी। और जैसा कि डेलरूस बानो बेगम बनाम में बताया गया है। नवाब स्यूद अशगुर सहयोगी खान (1), यह तय करने में ध्यान देने योग्य कारक है कि कोई दान निजी है या सार्वजनिक, चाहे पूजा का स्थान स्थित हो।

किसी निजी घर या सार्वजनिक भवन के अंदर। दूसरा, यह स्वीकार किया जाता है कि कुछ मूर्तियों को मंदिर परिसर के भीतर एक आसन पर स्थायी रूप से स्थापित किया जाता है। यह निजी होने के बजाय सार्वजनिक होने के साथ अधिक सुसंगत है। तीसरा, मंदिर में पूजा एक अर्चक द्वारा की जाती है जिसे मंदिर से समय-समय नियुक्त किया जाता है और अंत में, यह तथ्य है कि गाँव में कोई मंदिर नहीं था, और वादी की ओर से सबूत है कि ठाकुरद्वारा था ग्रामीणों के आग्रह पर उनके लिए पूजा स्थल प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस साक्ष्य पर नीचे की

अदालतों द्वारा विचार नहीं किया गया है, और यदि यह सच है, तो यह साबित करने के लिए निर्णायक होगा कि सार्वजनिक धर्मदाय है।

इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि वादी ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया कि मंदिर था "आम जनता की पूजा के लिए" समर्पित, पहले प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में केवल यह अनुरोध किया कि ठाकुरद्वारा और मूर्तियाँ निजी थीं। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि मंदिर की स्थापना परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए की गई थी। प्रकरण में, जबकि वादी के गवाहों ने बयान दिया कि मंदिर का निर्माण सभी हिंदुओं के लिए पूजा स्थल प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, प्रतिवादियों द्वारा जांचे गए गवाहों ने केवल यह बयान दिया कि शिव गुलाम ने ठाकुरद्वारे का निर्माण अपने उपयोग के लिए और "केवल अपनी पूजा के लिए" किया था। निचली अदालत का यह विचार कि मंदिर को परिवार के सदस्यों को समर्पित माना जाना चाहिए, अभिवचन से परे है और मामले में साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि भद्रेसिया में श्री राधाकृष्णजी का ठाकुरद्वारा एक सार्वजनिक मंदिर है।

परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है। नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेश को रद्द कर दिया गया था और वाद के पैरा 17 (ए) के संदर्भ में एक घोषणा दी गई है। सभी न्यायालयों में अपीलार्थी की

लागत न्यास की संपत्तियों से आएगी। पहला प्रतिवादी स्वयं अपना पूरा खर्च वहन करेगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हरीश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।